ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 11, Issue 5, September - October 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.583

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

भारत में नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. प्रेम सिंह रावलोत – सह–आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर– (राजस्थान)

पल्लवी चौहान – शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, भूपाल नोबल्स विश्वविद्यालय, उदयपुर– (राजस्थान)

सारांश

नक्ससलवाद की समस्या भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा समस्या है क्योंकि इसके प्रभाव बहुस्तरीय हैं। माओवादी आंदोलन भारत की आंतरिक कमजोरियों को उजागर करता है, जो भारत को बाहरी खतरों के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। वैश्वीकरण के के इस दौर में, नक्सली आंदोलन जैसे खतरों को अब केवल आंतरिक खतरे के रूप में नहीं देखा जा सकता है क्योंकि यह बाहरी सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। यह शोध–पत्र वर्तमान परिदृश्य में नक्सलवाद के मूल और कारण को स्पष्ट रूप से उजागर करने का प्रयास करता है। यद्यपि भारत सरकार ने इस समस्या से प्रभावित जनसंख्या वर्ग के संदर्भ में अनेक सकारात्मक प्रयास समय–समय पर किए है, परंतु वर्तमान समय में समस्या यह है की इन कानूनों और प्रावधानों को अलग–अलग जनसमूह तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकता है। नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा और और एक बड़ी चुनौती है। भारत में नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद की श्रेणी में एक बडी समस्या के रूप में देखा जाता है। देश में नक्सल हिंसा की बढ़ती हुई घटनाएं चिन्ताजनक है क्योंकि इन घटनाओं से मानवाधिकार का उल्लंघन तो होता ही है साथ ही साथ देश का सर्वांगीण विकास और संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। देश में नक्सलवाद को वामपंथी उग्रवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र में भारत में नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित प्रमुख राज्यों का विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द : नक्सलवाद, आंतरिक सुरक्षा, माओवादी आंदोलन,

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

परिचय :

नक्सल समस्या देश की आंतिरक सुरक्षा के लिए सबसे बडा खतरा तो है ही अत्यधिक हिंसा की वजह से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास भी अवरुद्ध है। देश में नक्सली गतिविधियां आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में व्याप्त है। देश के करीब 40 प्रतिशत भू–भाग और करीब 35 फीसदी आबादी नक्सलवाद से पीड़ित है। देश में करीब चालीस ऐसे समूह हैं जो नक्सलवादी विचारधारा को सही कहते हैं, जिसमें मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवादी शामिल हैं। इसमें 11 संगठन ऐसे हैं जिनको नक्सलवादी आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है और उन्हें वामप ंथी उग्रवाद की श्रेणी में रखा जाता है।

नक्सलवाद की शुरूआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन के रूप में हुई थी। लेकिन पचास वर्षों में ही नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। माओवादी विचारधारा से प्रेरित माओवादी आंदोलन को नक्सल आंदोलन और इससे जुड़े लोगों को, नक्सली कहा जाता है क्योंकि माओवादी विचारधारा से प्रेरित कम्युनिस्ट नेता चारु मजूमदार और कानू सान्याल द्वारा जमींदारों और फिर सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत नक्सलबाडी से ही की गई थी। नक्सली मूल रुप से माओवादी है और उनका दृढ़ विश्वास है कि सत्ता की चाबी बंदूक की नली से होकर निकलती है।

अध्ययन के उद्देश्य :

- देश में नक्सलवाद की समस्या का विश्लेषण करना
- प्रमुख राज्यों में नक्सलवाद की समस्या के स्तर का विश्लेषण करना
- अन्य राज्यों में नक्सलवाद के बढ़ते स्तर का मूल्यांकन करना

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

शोध विधि एवं आंकड़ों के स्रोत :

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्यतया द्वितीयक आंकड़ो की सहायता से तैयार किया गया है। इस हेतु विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रकाशित रेपोर्ट्स, पुस्तकों एवं अन्य शोध–पत्रों का अध्ययन कर सहायता ली गयी है साथ ही नवीन आकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों से भी संदर्भ लिए गए है।

नक्सलवाद का विकास :

नक्सलबाडी से शुरू होकर धीरे–धीरे नक्सलवाद ने पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार, उडीसा, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों को प्रभावित किया और वर्तमान में देश के दस राज्य इसके प्रभाव क्षेत्र में है। देश के जिन राज्यों में नक्सलवादियों ने अपना प्रभाव जमाया हुआ है वे राज्य हैं– छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त पीपुल्सवार और एमसीसी तामिलनाडु, केरल और कर्नाटक में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश में है। उग्रवाद प्रबंधन संस्थान के अनुसार वास्तव में यह समस्या देश के 14 राज्यों के 165 से अधिक जिलों तक फैली हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वामपंथी उग्रवाद चिन्ता का विषय बना हुआ है। जहां देश के दस राज्यों के 106 जिले अलग–अलग स्तर पर वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित है वहीं 7 राज्यों के 35 जिले सर्वाधिक प्रभावित है। नक्सलवाद ने अपनी शुरूआत से ही देश के कई राज्यों तक अपना विस्तार किया है लेकिन इस समस्या ने अपनी शुरूआत के पांच दशकों के उपरांत छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा के दृष्टिकोण से देश का केन्द्र बिंदू बना दिया है। वर्ष 2010 से लेकर 15 जून 2017 तक देश में कुल 10188 नक्सली वारदातें हुई जिसमें कुल 3922 लोगों की मौतें हुई, जिसमें सर्वाधिक 1167 लोगों की मौत छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है जो उपरोक्त अवधि के दौरान नक्सल हिंसा की वजह से हुई कुल मौतों का 34.40 प्रतिशत है। वर्ष 2009 से 2013 के बीच छत्तीसगढ़ राज्य में हुई कुल मौतों में से 853 मौत केवल बस्तर संभाग में हुई, जो राज्य में हुई कुल मौतों का 95.30 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सली हिंसा का केन्द्र बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित सात जिले हैं, जो संचार के आधुनिक सुविधाओं से करीब करीब पूरी तरह से वंचित है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ो के अनुसार यहां के एक प्रतिशत परिवारों को भी टेलिफोन और इंटरनेट की

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

सुविधा उपलब्ध नहीं है और संचार क्रांति के इस दौर में केवल 1.43 प्रतिशत परिवार कंप्यूटर से परिचित हैं। संप्रेषण के अन्य माध्यमों की बात करें तो भी बस्तर संभाग के शहरी आबादी को छोड कर करीब–करीब पूरा बस्तर संभाग टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया और अन्य सुविधाओं की पहुंच से दूर है। शासन के साथ बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों का संवाद बाधित है और हिंसा की वजह से संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में संप्रेषण की नैसर्गिक प्रक्रिया भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद का विस्तार 80 के दशक के बाद शुरू होता है। इसी साल पीपुल्सवार की स्थापना के बाद कोंडापल्ली सीतारमैया ने सशस्त्र गुरिल्लाओं को देश के अन्य जंगलों में भेजने के साथ ही बस्तर में भी आधार क्षेत्र स्थापित करने के लिए भेजा था। इसके बाद से लगातार नक्सलियों ने राज्य में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया है और नक्सली घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। दरभागुड़ा, रानीबोदली, तालमेटला, सिंगारम और जीरम हमले जैसी नक्सली घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लगातार बढ़ती नक्सल हिंसा के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भय और आतंक का ऐसा वातावरण बन गया है जो संप्रेषण की नैसर्गिक प्रक्रिया को बाधित कर रहा है। प्रभावित क्षेत्र में संप्रेषण की भौतिक बाधाएं तो दिखाई देती ही हैं, संप्रेषण की व्यैक्तिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी चरम पर प्रतीत होती है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का परिचय :

राष्ट्रीय संदर्भ में नक्सलवाद के बढ़ते खतरे का परिणाम है कि देश के 10 राज्यों के 106 जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे जिलों में अधिकांश विकास की प्रक्रिया में पिछड़े हुए आदिवासी बहुल वनाच्छादित क्षेत्र हैं। इन भौगौलिक क्षेत्रों की स्थिति इतनी विषम है कि नक्सलवाद का भय एवं गतिविधियां यहां तेजी से फैली हैं, फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में नक्सली हिंसा की घटनाएं व्यापक और जटिल रूप ले चुकी हैं। इस हिंसा को वामपंथी उग्रवाद जनित हिंसा का नाम भी दिया जाता है। वर्तमान में भारत का लगभग 40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 35 प्रतिशत जनसंख्या पर वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अनुसार देश में सशस्त्र नक्सलियों की संख्या बीस हजार से अधिक है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

यह माना जाता है कि देश के 106 जिलों में नक्सलियों का प्रभाव है उन क्षेत्रों को मिलाकर नक्सलियों ने भारत को बीच से बांटते हुए लाल गलियारा निर्मित किया है। इसके लिए नक्सलियों ने इन क्षेत्रों मे अपना मुक्त और आधार क्षेत्र स्थापित किया है और इन्हीं क्षेत्रों में नक्सलियों की सर्वाधिक मौजूदगी है। नक्सलियों के प्रभाव वाले इन क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर अथवा लाल गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। लाल गलियारे का अधिकांश क्षेत्र सर्वाधिक गरीबी का शिकार है और इसका ज्यादातर हिस्सा वनाच्छादित है। यहां अधिकांश आदिवासी हैं। लाल गलियारे के अन्तर्गत आने वाले बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्य देश के सर्वाधिक गरीब राज्यों में शामिल किए जाते हैं जबकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के सामान्य और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता की गहरी खाई है। मानव विकास सूचकांक के दृष्टिकोण से भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र अत्यन्त पिछड़े हुए हैं।

नक्सल प्रभावित अधिकांश क्षेत्र संचार की सुविधाओं से पिछड़े हुए हैं। नक्सल प्रभावित कई विकासखंडों तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा काम है और इन क्षेत्रों में अधिकांश गरीब किसान और आदिवासी निवासरत है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र देश के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र है और यहां अधिकांश अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो सामान्य ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं से भी वंचित हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत अधिकांश किसान खेतिहर मजदूर हैं क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं है। जबकि वनाच्छादित क्षेत्रों में रहनेवाले आदिवासियों के जीवन यापन का मुख्य जरिया वनोपज का संग्रहण है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की करीब 40 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है अथवा आधा एकड़ से कम है। इसके अलावा आजीविका, न्यूनतम मजदूरी या दिहाड़ी, सामाजिक दमन, बंधुआ मजदूरी, कुशासन या गैर–प्रशासन के कारण रोष व गुस्सा आदि ऐसे मुद्दे और स्थितियां है, जिन्होंने नक्सल आंदोलन को मजबूत किया है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

भारत के सात राज्यों के ऐसे ही आर्थिक और सामाजिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े हुए 35 जिलों को जहां नक्सलियों का अत्यधिक प्रभाव है, सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की श्रेणी में रखा गया है जबकि 88 जिलों को नक्सलियों के सामान्य प्रभाव का क्षेत्र माना गया है । इसके अतिरिक्त 18 जिलों को नक्सलियों के आंशिक प्रभाव का क्षेत्र माना गया है जिसके मद्देनजर सरकार के एस.आर.ई स्कीम (सिक्युरिटी रिलेटेड एक्सपेंडीचर स्कीम) के तहत देश के कुल 106 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। एस.आर.ई स्कीम के तहत देश के 10 राज्यों के जिन 106 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों के रूप में शामिल किया गया है वे राज्य और जिले इस प्रकार है।

मानचित्र : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और लाल गलियारा

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

तालिका संख्या 01
भारत सरकार के एस.आर.ई योजना के तहत चयनित राज्य और जिले

क्रं.स.	राज्य	जिलों की संख्या	एस.आर.ई स्कीम के तहत चयनित जिले
1	आन्ध्रप्रदेश	8	अनंतपुर, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कुरनूल, प्रकासम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम।
2	तेलंगाना	8	अदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, मेडक, महबूबनगर, नलगोंडा, वारंगल और निजामाबाद।
3	बिहार	22	अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मूंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सितामढ़ी, पश्चमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवहर, वैशाली, बांका, लखीसराय, बेगुसराय और खगड़िया।
4	छत्तीसगढ	16	बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोंडागांव और बलरामपुर।
5	झारखंड	21	बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरीडीह, गुमला, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदग्गा, पलामू, रांची, सिमडेगा, खूंटी, सराईकेला–खरसवान, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, देवघर और पाकूर।
6	मध्यप्रदेश	1	बालाघाट।
7	महाराष्ट्र	4	चन्द्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया और अहेरी।
8	ओडिसा	19	गाजापट्टी, गंजम, क्योंझर, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगडा, संबलपुर, सुंदरगढ़, नयागढ़, कंधमाल, देवघर, जाजपुर, ढेंकनाल, कालाहांडी, नुवापारा, बरगड़ और बलांगिर।
9	उत्तरप्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र।
10	पश्चिम बंगाल	4	बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरूलिया और वीरभूम।

स्त्रोतः– लोकसभा प्रश्नावली

उपरोक्त 106 जिलों में से 88 नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार ने एकीकृत कार्ययोजना स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से आईएपी जिलों में एक साथ आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। देश भर से एकीकृत कार्ययोजना के तहत चयनित नक्सल प्रभावित जिलों की आधारभूत जानकारी इस प्रकार है।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

तालिका संख्या 02
देश में नक्सल प्रभावित जिलों की आधारभूत जानकारी

क्रं.स.	राज्य	जिलों की संख्या	ब्लाक की संख्या	पंचायत की संख्या	गांव की संख्या	प्रभावित जनसंख्या
1	आन्ध्रप्रदेश	4	169	3957	7878	15294
2	बिहार	11	145	2179	13020	28784
3	छत्तीसगढ़	14	96	4959	11677	58983
4	झारखंड	17	170	3162	18239	82969
5	मध्यप्रदेश	10	66	4624	10713	34065
6	महाराष्ट्र	4	42	2411	4666	6309
7	ओडिसा	18	207	3767	30223	83591
8	तेलंगाना	4	205	3834	5371	12593
9	उत्तरप्रदेश	4	29	1880	4527	9058
10	पश्चिम बंगाल	3	71	648	12988	25752
कुल		88	1200	31421	119302	357398

स्त्रोत– http://iapmis-planningcommission-nic-in/basic_info-asp

उपसंहार :

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है की नक्सलवाद की समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर मुद्दा है, यद्यपी केन्द्र सरकार देश के दस राज्यों के 106 जिलों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में मानती है जबकि स्वतंत्र विश्लेषकों के अनुसार स्थिति और ज्यादा गंभीर है। वर्तमान में नक्सलियों का आतंक देश के 13 राज्यों और करीब 170 जिलों में फैल चुका है। देश में नक्सलवाद की समस्या इतनी बिकराल और विस्तारित हो गई है कि अब इसकी तुलना में काश्मीर की समस्या छोटी दिखाई पड़ने लगी है। वास्तव में 13 राज्यों के 170 जिलों, 45 करोड़ आबादी और 40 फीसदी क्षेत्रफल को प्रभावित करने वाला नक्सली आंदोलन रक्षा विशेषज्ञों तथा विचारकों की दृष्टि से काश्मीर के आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश तो नक्सल

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 5, September-October 2024 |

प्रभावित राज्यों की श्रेणी में शामिल है ही, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरांचल और हरियाणा में भी नक्सली अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. बाबू, डॉ.जे.मधु, – न्यूजपेपर एंड नक्सलाईट मूवमेंट, कनिष्क पब्लिशर्स– डिस्ट्रीब्यूटर्स, 4697/5/ 21 ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 110002, वर्ष 2010, पृष्ठ–1.
2. तिवारी, डॉ. मुकेश कुमार, – नक्सलवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक विश्वास, विश्व भारती पब्लिकेशन, एचआईजी, एच–24, तीसरी मंजिल, बाईपास रोड, आगरा, 282004, वर्ष 2012–13, पृष्ठ–37.
3. बाबू, डॉ.जे.मधु, – न्यूजपेपर एंड नक्सलाईट मूवमेंट, कनिष्क पब्लिशर्स– डिस्ट्रीब्यूटर्स, 4697/5/ 21 ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 110002, वर्ष 2010, पृष्ठ–16.
4. सक्सेना विवेक, सुशील राजेश, – नक्सली आतंकवाद, प्रभात प्रकाशन, 4/11, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 110002, वर्ष 2010, पृष्ठ–142
5. तिवारी, डॉ. मुकेश कुमार, – नक्सलवाद, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक विश्वास, विश्वभारती पब्लिकेशन, एचआईजी, एच–24, तीसरी मंजिल, बाईपास रोड, आगरा, 282004, वर्ष 2012–13, पृष्ठ–19.
6. योजना आयोग रिपोर्ट–2008, भारत सरकार, नई दिल्ली.
7. सक्सेना विवेक, सुशील राजेश, नक्सली आतंकवाद, प्रभात प्रकाशन, 4/11, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, 110002, वर्ष 2010, पृष्ठ–93. 9.
8. लोकसभा प्रश्नावली, प्रश्न क्रमांक 1374, 05.03.2013

IJARASEM

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com